

59



अमर्ष :- न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी क्र. /2018

निगरानी-4035/2018/बैतूल/2018

श्री योगेश्वर सिंह मदी
द्वारा आज दि. 2-7-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क प्रेषित।
दिनांक 10-7-18
कलर्क ऑफ कोर्ट 2-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. सुन्दरलाल सूर्यवंशी, आयु-लगभग 61 वर्ष, पिता-स्व.रामपत सूर्यवंशी, जाति - किनाड़, निवासी - अवस्थी कॉम्प्लेक्स के पीछे, कॉलेज रोड बैतूल, तह. व जिला-बैतूल (म.प्र.)
2. राजा सूर्यवंशी, आयु-लगभग 32 वर्ष, पिता-सुन्दरलाल सूर्यवंशी, जाति - किनाड़, निवासी - अवस्थी कॉम्प्लेक्स के पीछे, कॉलेज रोड बैतूल, तह. व जिला-बैतूल (म.प्र.)

.....निगरानीकर्तागण

विकरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा अपन कलेक्टर बैतूल, तहसील व जिला-बैतूल (म.प्र.)
2. तहसीलदार बैतूल, तहसील व जिला-बैतूल

.... गैरनिगरानीकर्तागण

Y. Shaper
योगेश्वर सिंह मदी
10/7/2018

निगरानीकर्ता, ग्वालियर
दि. 4/8
से 15
+ 22-07-18
र व नाम...

अभ्यावेदन / निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व अधिता 1959:-

निगरानीकर्तागणों की ओर से निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है :-

उक्त निगरानी कार्यालय कलेक्टर बैतूल की ओर से अपन कलेक्टर बैतूल के द्वारा तहसीलदार बैतूल को प्रेषित पत्र क्र. 50208 बैतूल दिनांक 24.04.2018 (एनेक्सर ए-1), एवं कार्यालय कलेक्टर बैतूल के पत्र क्र. 5183 बैतूल दिनांक 27.04.2018- (एनेक्सर ए-2), एवं अपन कलेक्टर बैतूल के द्वारा पारित आदेश पत्रिका दिनांक 08.05.2018 (एनेक्सर ए-3), अहित न्यायालय तहसीलदार बैतूल के अमर्ष लम्बित न.मा.क्र. 0039/अ-68 वर्ष 2017-18 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 10.05.2018 अहित अन्य आदेश पत्रिकाएं (एनेक्सर ए-4) से क्षुब्ध होकर माननीय मण्डल के अमर्ष उपरोक्त अभ्यावेदन/निगरानी विधिवत सुनवाई हेतु प्रस्तुत है।

Signature

Signature

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4035/2018/बैतूल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-2018	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार ने आदेशिका दिनांक 10-5-18 द्वारा आवेदक पक्ष के विरुद्ध उनके न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में अपर कलेक्टर के पत्र दिनांक 24-4-18 के अनुसार प्रकरण संलग्न किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्रहय की जाती है ।</p>	<p>अध्यक्ष</p>